www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 129 नागपुर, बुधवार, 5 अप्रैल 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना का जवान गिरफ्तार, बैग में मिला जिंदा कारतूस

श्रीनगर

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जवान से दो ग्रेनेड मिलने के अगले दिन ही इसी एयरपोर्ट पर एक और जवान को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक जवान के पास से एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। आरोपी जवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

जांच अधिकारी ने बताया कि सैनिक पांडिया राज श्रीनगर से दिल्ली के लिए आ रहा था। उसे जांच पड़ताल के लिए आर्मी अधिकारियों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह लगता है कि कारतूस जवान के बैग में गलती से रह गया होगा।

बता दें इससे पहले सोमवार को सुरक्षा कर्मियों ने सेना के एक जवान को दो जिंदा बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इन बमों को लेकर वह नई दिल्ली जाने वाले एक विमान में सवार होने वाला था।

तनाव कम करने आगे आया अमेरिका, भारत पाक के लिए शांतिदूत बनेंगे ट्रंप !

नई दिल्ली

अमेरिका ने कहा है कि वह भारत-पाक तनाव को कम करने में अपनी भूमिका तलाशेगा। वह कुछ बुरा होने की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अमेरिका के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रयास में भूमिका निभा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने मंगलवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जारी विवाद में अमेरिकी रुख में बदलाव होने का संकेत दिया। अमेरिका ने अभी तक खुद को दूर ही रखा है। हेली ने कहा, यह एकदम सच है कि वर्तमान प्रशासन भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को लेकर चिंतित है। प्रशासन इस विवाद को कम करने का उपाय तलाशेगा।

भारतीय-अमेरिकी हेली ट्रंप कैबिनेट की वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन बातचीत करेगा और तनाव कम करने में अपनी भूमिका की तलाश करेगा। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें कुछ होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए।

संवाददाताओं ने उनसे पूछा था कि भारत और पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए अमेरिका तैयार कर सकता है? दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे पर जारी विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिकी राजदूत ने कहा, जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उस स्थिति में हमें सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि टकराव के बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं और इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम शांति कायम कर सकते हैं या नहीं।

श्रद्धा *श्री पोद्दारेश्वर राममंदिर से रामनवमी निमित्त रामजन्मोत्सव पर मंगलवार को निकली शोभायात्रा के शुभारंभ अवसर पर प्रभु श्रीराम, जानकी व लक्ष्मण के श्रीविग्रहों का पूजन कर आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं असम के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित।*

31 मार्च तक पंजाब के 19 लाख पेंशनरों के बकाया जारी करें - कैप्टन अमरेंद्र सिंह

चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को 19.08 लाख लाभपात्रों की पेंशन के 31 मार्च तक का बकाया जारी करने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही कैप्टन ने 1 अप्रैल, 2017 से योग्य लाभपात्रों की पड़ताल करने के लिए नई विधि प्रयोग में लाने के लिए कहा है। यहां सामाजिक सुरक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के नवंबर महीने से सभी पेंशन बैंकों के द्वारा मिलेंगी, जिससे पेंशन देने की प्रक्रिया आसान होने के अलावा निर्विघ्न अदायगी की जा सकेगी।

मीटिंग में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, सामाजिक सुरक्षा विभाग के मुख्य सचिव और डायरेक्टर उपस्थित थे।

सरकारी वक्ता ने बताया कि मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया है कि मौजूदा लाभपात्रों की जांच की जाए, जिससे जाली या अयोग्य लाभपात्रों को निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने योग्यता के नए मापदंड और पड़ताल प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए। अलग-अलग सरकारी विभागों में विकलांग व्यक्तियों की खाली पड़े पदों संबंधित भी विचार किया गया।

तमिलनाडु: सूखा प्रभावित किसानों को राहत, कोर्ट ने कर्जमाफी का दिया आदेश

चेन्नई

सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों की कर्ज माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दे दिया है। करीब एक महीने से तमिलनाडु के किसान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बाद इनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भी आ गई है।

भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि सरकारें किसानों की सुध नहीं ले रही हैं। बता दें कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के नेता और दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता ने भी इन किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठायी।

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी अर्धनग्न अवस्था में तो कभी मरे हुए सांपों को जीभ पर रखकर प्रदर्शन किया। जिसके जरिए वे किसानों की दयनीय हालात को केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं कि कर्ज के बोझ से किसान मर रहे हैं।

पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रदर्शन कर रहे इन किसानों से मुलाकात की और केंद्र सरकार से इनकी कर्ज माफी की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन

उन किसानों का क्यों नहीं, जिन्होंने यह देश बनाया है। इनकी आवाज न ही प्रधानमंत्री को सुनाई देती है और न ही हिंदुस्तान की सरकार को, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इनकी बात को सुनें।

किसानों का कहना है कि खराब आर्थिक हालत के चलते कर्ज से परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों की शिकायत है कि सरकार तमिलनाडु के खेतों को कावेरी नदी का पानी नही दे रही है। इसकी वजह से उनके खेत भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं। इस सूखे के चलते उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाला है।

प्रदर्शनकारी किसान तमिलनाडु के लिए केंद्र से 40 हजार करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज, ऋण माफी एवं अन्य राहत की मांग कर रहे हैं।

यूपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला

किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ

लखनऊ

नयी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिये बड़ा फैसला किया गया है। किसानों के एक लाख तक के कर्ज माफ किये गये हैं। करीब डेढ़ घंटे तक चली पहली बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गये हैं। बैठक के बाद अब प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों के बारे में जानकारी दी जायेगी।

विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के किसानों से किये गए वादे को योगी आदित्यनाथ सरकार की होने जा रही कैबिनेट की पहली बैठक में निभाने जा रही है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सूबे के लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को लखीमपुर खीरी के राजकीय इंटर कालेज मैदान में

आयोजित चुनावी रैली में एलान किया था कि भाजपा सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लिहाजा योगी सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज के बोझ से कराहते अन्नदाताओं के फसली ऋण को माफ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए उन्हें राहत देने का इंतजाम करेगी।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने फिलहाल 31 मार्च 2016 तक लघु व सीमांत किसानों द्वारा लिये गए फसली ऋण में से उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान की गई राशि को घटाते हुए अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक के कर्ज माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा सरकार लघु व सीमांत किसानों के गैर निष्पादक ऋणों का भी भुगतान करेगी।

इस प्रस्ताव पर मुहर लगने से सूबे के तकरीबन 86 लाख लघु व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने पर सरकार पर तकरीबन 36,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आएगा।

कर्ज माफी की योजना बनाने गठित होगी समिति

लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण को माफ करने की योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है। यह समिति कर्जमाफी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने के उपाय सुझाएगी और योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय तय करेगी।

उत्तरप्रदेश में 2.33 करोड़ किसान हैं। इनमें 1.85 करोड़ सीमांत और लगभग तीस लाख लघु किसान हैं। इस हिसाब से सूबे में लघु व सीमांत किसानों की संख्या 2.15 करोड़ है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

भारत में अफगान शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा होगी पूरी

नई दिल्ली

अफगानिस्तान में कई दशकों से चले आ रहे संघर्ष के कारण शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। कई अफगानी नागरिकों ने अपना घर छोड़ पाकिस्तान, भारत, मध्यपूर्व और यूरोप में शरण ले ली। नई दिल्ली में लगभग 10,000 अफगान शरणार्थी हैं।

भारत आयी अफगानी छात्रा सारा ने बताया, भारत और अफगानिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में काफी अंतर है। अफगानिस्तान में शिक्षक पढ़ाने के दौरान बच्चों को पीटते हैं जो पढ़ाने का काफी गलत तरीका है। भारत में अनेकों संस्थान इन शरणार्थियों के बच्चों को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें से एक है ब्रिजेज अकेडमी।

शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है गोवा सरकार - पर्रिकर

पणजी

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राज्य सरकार राजमार्गों पर शराब पर पाबंदी के आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर्यटक राज्य के लिए शीर्ष अदालत से विशेष रूप से ध्यान देने का भी अनुरोध कर सकती है। पर्रिकर ने संवाददाताओं से कहा, 31 मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश सुनाने के बाद बंदी की आशंका झेल रही (गोवा में) लगभग 3000 में से करीब 1000 दुकानों को राहत

मिली।

गोवा को मिले कुछ विशेष छूट

मुख्यमंत्री ने कहा, अब मुद्दा केवल 2000 दुकानों का है। गोवा सरकार को लगता है कि राज्य को कुछ विशेष छूट दी जानी चाहिए, लेकिन यह अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। शीर्ष अदालत जाने के लिए हमें उचित ढंग से दस्तावेज तैयार करने होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आदेश का विश्लेषण शुरू कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 31 मार्च को अपने आदेश में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया था।

अदालत ने 20,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यह दूरी घटाकर 220 मीटर कर दी थी।

एलओसी पर पाक की फायरिंग का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

राजौरी

जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हल्के और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए। गौरतलब है कि सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने वहां मौजूद भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को तलब कर भारत पर सीमा पार से गोलाबारी करने और इसमें मासूमों की जान लेने का आरोप लगाया था।

पाकिस्तान के डीजी डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सिंह को बुलाकार इस तरह की कार्रवाई की आलोचना की। इतना ही नहीं पाकिस्तान ने भारत पर चिरीकोट में सीजफायर उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया।

हाइवे शराबबंदी: सरकारी अधिकारियों ने राजमार्गों को डिनोटिफाइ करना शुरू किया

नई दिल्ली

नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राज्य सरकारों ने तुरंत काट निकालते हुए स्टेट हाइवे को डिनोटिफाइ करना शुरू कर दिया, वहीं राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाइवे को भी डिनोटिफाइ करने की तैयारी है। हालांकि, जानकार मानते हैं कि ऐसा कदम राज्य सरकारों के लिए ही भारी पड़ सकता है।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, वह कोर्ट से इस मामले में किसी तरह की नरमी बरतने की दरख्वास्त नहीं कर सकती। उसे डर है कि ऐसा करने पर उसे कोर्ट की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी मंत्रालय ने खुद हाइवे के किनारे शराब की दुकानों पर बैन लगाने की वकालत की थी। शराब के नशे में होने वाले सड़क हादसों को इसका कारण बताया गया था।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अक्टूबर 2007 में अडवाइजरी

जारी करके नेशनल हाइवे के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। इसके अलावा यह भी कहा था कि नए लाइसेंस न दिए जाएं। वहीं, मंत्रालय की नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल ने जनवरी 2004 में सुझाव दिया था कि नेशनल हाइवे के किनारे शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस न दिए जाएं।

परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी राज्य सरकार ने नेशनल हाइवे को डिनोटिफाइ करने की दरख्वास्त नहीं दी है। उसे एक सांसद की ओर से खत मिला है, जिसमें दमन से गुजरने वाले नेशनल हाइवे को डिनोटिफाइ करने की दरख्वास्त की गई है। हालांकि, मंत्रालय ने उनकी इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवहन मंत्रालय को लगता है कि अगर सांसद की यह मांग मान ली गई तो यह केंद्र शासित प्रदेश अपना इकलौता एनएच भी गंवा देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बचने के लिए सड़कों को डिनोटिफाइ करने के मामले में राज्य सरकार के पास सीमित विकल्प हैं। राज्य सरकारें चाहती हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे का दर्जा मिले, ताकि केंद्र सरकार के खर्च पर उसकी मरम्मत और रखरखाव हो सके। इसके अलावा, अगर वह किसी नेशनल हाइवे को डिनोटिफाइ करवाती है तो उसकी मरम्मत का खर्च भी उसे ही उठाना पड़ेगा।

जानकार मानते हैं कि किसी नेशनल हाइवे के किनारे स्थित दुकानों से जितना राजस्व मिलता है, उससे ज्यादा खर्च तो इन सड़कों की मरम्मत पर आएगा, वहीं करीब-करीब सभी नेशनल हाइवे के किनारे शराब की दुकानें हैं, ऐसे में सभी को डिनोटिफाइ करना मुमकिन नहीं है। तय नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार किसी हाइवे की मरम्मत तभी करवा सकती है, जब वह नेशनल हाइवे के तौर पर नोटिफाइ हो। वहीं, अधिकतर नेशनल हाइवे को या तो चौड़ा किया जा रहा है या उन्हें किया जाना है, ऐसे में डिनोटिफाइ करते ही सारा खर्च राज्यों पर आ जाएगा।

महाराष्ट्र में भी हो सकता है किसानों का कर्ज माफ

मुंबई

महाराष्ट्र के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि राज्य की भाजपानीत सरकार भी किसानों की कर्जमाफी पर विचार कर रही है। उन्होंने यह बात उत्तरप्रदेश में किसानों की कर्जमाफी घोषित होने के संदर्भ में कही है।

उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कर्जमाफी के वादे के बाद से ही विपक्षी दलों द्वारा महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की जा रही है। शिवसेना सहित भाजपा के मित्र दलों द्वारा भी यह मांग जोरशोर से उठाई जा रही है। ऐसे में एक मराठी चैनल से बातचीत में मुनगंटीवार ने कहा कि भाजपा सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा

किया जाता है। जैसे उत्तरप्रदेश में वादा पूरा किया गया है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्जमुक्ति को लेकर सरकार की सोच सकारात्मक है।

सिर्फ यह विचार किया जा रहा है कि किसानों को कर्जमुक्ति कब और कैसे दी जाए। महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति उत्तरप्रदेश से ज्यादा खराब है। बता दें कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत पड़ेगी।